

ग्रसाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग І-खण्ड 1

PART I-Section I

प्राधिकार से प्रकारित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]

नई बिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 1968/माघ 17, 1885

No 21]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 1968/MAGHA 17, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास पंत्रालय (पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1968 विषय:-एक पुतर्वास बोड की स्थापना

संख्या 3(5)/67-श्रार० ए ब०-v:--1916 से लेकर आज तक इस जिस को पिकस्तान से भारी संख्या में आने वाले अल्प-संख्यकों का बताने के कार्य का सामना कपना पह रहा है। पिचम पिक्स्तान से आये अधिकाश विस्थापित व्यक्तियों के भूमि पर, तथा छाटे-म टे कार प्राप्त व्यापाप से बनाया जा चुका है किन्तु जहां तक पूर्वी-पिकिस्तान से आने वाले विस्था कि व्यक्तियों की महायता तथा पुनर्वास का सम्बाद है, यह अभी तक्त पापत एकार तथा कार्य सरकारों के लिये एक मुख्य समस्या और जिस्मेदारों वना हुई है। ऐसा श्राप्त है के प्राप्त के की ऐसे विदेशों ने तथा है की विस्थापित व्यक्तियों और विदेशों ने तथा है की क्यापात व्यक्तियों और विदेशों ने तथा है है कि विस्थापित व्यक्तियों और विदेशों ने तथा है कि विस्थापित व्यक्तियों और विदेशों ने तथा कि स्थित है कि विस्थापित व्यक्तियों और विदेशों ने तथा कि स्थापित व्यक्तियों और विदेश से लीटने वाले भारतीयों को बसाने के लिये केन्द्रीय प्राप्त अविष्य में केवल उद्याग तथा उससे सम्बन्धित

कार्यक्रम, विशेषकर एकीकृत क्षेत्र की विकास योजनाओं पर ही निर्भर होगा । उद्योग में विशेषकर प्रादेशिक विकास कार्यक्रम होँगे ("विशेष क्षेत्र") जिनमें दिण्डकारण्य, ग्रम्बमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चान्दा जिला (महाराष्ट्र) माते हैं।

2. लगभग दस लाख से भ्रधिक व्यक्तियों के पुनर्ध्यवस्थापन तथा एकीकरण की चली भ्रा रही भ्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने एक पुनर्वास-बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है। इस बोर्ड में राष्ट्रीय नेता भ्रीर उद्योगपति होंगे जो सरकार को योजना तथा भ्रीद्योगिक श्रीर उससे सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार करने में सलाह देंगे।

## बोर्ड के विचारणीय विषय निम्न होंगे :---

- (1) पूर्वी पाकिस्तान से भागे विस्थापितों भीर बर्मा, श्रीलंका तथा भन्य देशों से लौटने वाले भारतीयों को उद्योगों तथा भ्रन्य गैर-कृषि कार्यत्रमों के श्रन्तर्गत पुनर्वास सम्बन्धी कार्य-नीतियों तथा उपायों के बारे में सलाह देना;
- (2) निम्नलिखित के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की मुख्य कठिनाइयों तथा समस्याश्रों के सम्बन्ध में गहन भ्रध्ययन:---
  - (क) विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटने वालों को उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण तथा श्रन्य गैर-कृषि कार्यक्रमों में पुनव्यवंस्थापन; श्रोर
  - (खा) वण्डकारण्य प्रायोजना क्षेत्र का स्रौद्योगिक विकास तथा स्रन्य क्षेत्र जिन्हें "विशेष क्षेत्र" घोषित किया जा चुका है।
- (3) निगम के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा चालू की गई योजनात्रों के कार्य तथा प्रगति का निश्चय करना;
- (4) निम्न के बारे में योजना तैयार करने तथा उसे कार्य रूप देने के लिये सरकार की सहायता करना :--

  - (ख) पुनर्वास उद्योग निगम, राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थानों श्रीर गैर-सरकारी श्रीद्योगिक तथा वाणिज्य उद्योगों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटने वालों के लिये उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण श्रीर गैर-कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत वसाने के लिये भावी कार्यक्रम श्रीर योजनाशों की रूप-रेखा निश्चित करना;
  - (ग) विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटने वालों को श्रव्धिक संख्या में रोजगार पर लगाने के लिये उद्योग तथा दस्तकारी को प्रोत्साहन तथा सुविधाएं देने के सम्बन्ध में व्यापक कार्य नीति;
  - (च) दण्डकारण्य तथा "विशेष क्षेत्र" [अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और चान्दा जिला (महाराष्ट्र)] में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिये आवश्यक उपाय।
- 4. बोईं का गठन निम्न प्रकार होगा :---

#### यम्पक

1. श्री मनुभाई शाह।

#### सरहरूप

- 2. श्री भ्राए० वैंकटारमन, सदस्य योजना भ्रायोग ।
- 3. श्री ए० के० सेन, इण्डियन श्रावसीजन लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-निदेशक ।
- 4. श्री के ॰ सी ॰ मैता, "गैस्ट, कीन विलियमस लिमिटेड", कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक।
- 5. श्री ए० एम० एम० प्रस्ताचलम, "ट्रयूब इन्बैस्टमेंट लिमिटेड, भारत",-मद्रास ।
- श्री डी० सी० कोठारी, उद्योगपति, मद्रास ।
- 7. श्री ई० डकास्टा, भारतीय लोकमत सस्था, नई दिल्ली के प्रबन्ध निदेशकः।
- 8. श्रौद्योगिक विकास तथा कम्पनी भागलों के मन्त्रालय (श्रौद्योगिक विकास विभाग) का एक प्रतिनिधि ।
- 9. वित्त मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि।

### सवस्य-सचिव

- 10. श्री बी० पी० सूद, संयुक्त मिचव, पुनर्वास विभाग।
- 5. बोर्ड को ग्रीर सदस्य बनाने का ग्रिधकार होगा किन्तु उनकी संख्या पांच से ग्रिधक न होगी! । जब कभी ग्रावश्यक होगा, भारत सरकार के सचिव, ग्रीर राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, सचिव तथा विभागों के ग्रध्यक्षों को सभा की बैठक से उपस्थित होने का ग्रनुरोध किया जायेगा । यदि बोर्ड ग्रावश्यक समझे तो ऐसे व्यक्तियों का भो निमन्त्रित करेगा, जैसे—व्यापार मण्डल ग्रीर उद्योग संघ, श्रीखल भारत व्यापारिक संगठन, प्रावेशिक व्यापार मण्डल तथा ग्रीद्योगिक संघ की संस्थाएं, राज्य व्यापार निगम, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड तथा रबड़ बोर्ड के ग्रध्यक्ष /सभापति ।
- 6. बोर्ड प्रपत्ती कार्य-प्रणाली ग्राप तैयार करेगा। बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये कार्य को चलाने के लिये सदस्यों में से, बोर्ड सिमितियों का गठन कर सकता है जिनमें बोर्ड द्वारा बनाये हुये सदस्य भी हो सकते है किन्तु उनकी संख्या सिमिति की एक तिहाई सख्या से अधिक नहीं हो सकती। जहा ग्रावण्यक होगा बोर्ड ग्रध्ययन, सर्वेक्षण ग्रादि करेगा या करवायेगा।
- गृ बोर्ड की सदस्यता अवैतिनिक होगी। गैर-सरकारी सदस्य, यात्रा तथा दैनिक भत्ता तथा अन्य सृविधाये जो भारत सरकार द्वारा मंजूर की जायेंगी, पाने के पात्र होंगे। सरकारी पदाधिकारियों की यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता सामान्य नियम, जो उन्हे लागू होते हैं, के अनुसार दिया जायेगा।
- 8. बोर्ड समय समय पर जब स्नावश्यक होगा, श्रपनी बैठक करेगा । बोर्ड का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा किन्तु बोर्ड जहा स्नावश्यक गमझेगा, उन स्थानों में जायेगा तथा ऐसे स्थानों से बैठकें भी करेगा ।
  - समय समय पर बोर्ड श्रपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

वी० नन्जप्पा, सचिव।

# MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (Department of Rehabilitation) RESOLUTION

New Delhi, the 5th February 1968

SUBJECT.—Constitution of a Board of Rehabilitation.

No. 3(5)/67-RH-V.—In continuation of the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 3(5)/67-RH-V. dated the 30th January, 1968, it has been decided to appoint Shri Kamalnayan Bajaj Member of Parliament, as a Member of the Board of Rehabilitation

V. NANJAPPA, Secy.